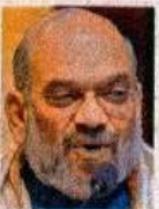


**65,000 सहकारी समितियां होंगी डिजिटल**

नाबार्ड चेयरमैन  
ने रखा लक्ष्य

■ दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क.  
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  
(नाबांड) के चेयरमैन शाजी के.वी. ने  
कहा कि सरकार का  
लक्ष्य सहकारी



कहा कि सरकार का लक्ष्य सहकारी समितियों की पारदर्शिता तथा दक्षता में सुधार के लिए अगले साल मार्च तक करीब 65,000 सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का है। नाबार्ड को राष्ट्रीय स्तर की निगरानी तथा कार्यान्वयन समिति और सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन व निर्देशों के तहत सहकारी समितियों को डिजिटल करने के लिए परियोजना प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है। सा-धन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि करीब

**NCOL** का 'आदत ऑर्गनिजिट्स' बांड जाएगी

 सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बव सुजित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) का 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड जारी किया। उन्होंने कहा कि यह भारत और विदेशों में सबसे 'भरोसेमंद' ब्रांड बनकर उभरेगा। शाह ने एनसीओएल का 'लोगो', वेबसाइट और ब्रोशर भी जारी किया। साथ ही उन्होंने 5 सहकारी समितियों को एनसीओएल सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए। शाह ने सहकारी समितियों के जरिए जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीओएल जैविक उत्पादकों के लिए एक मंच है। आज हम 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत 6 उत्पाद जारी कर रहे हैं और दिसंबर तक ऐसे 20 उत्पाद जारी होंगे। 6 जैविक उत्पाद अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसरी चावल होंगे।

10,000 सहकारी समितियों को पहले ही डिजिटल किया जा चुका है. हम मार्च 2024 तक 65,000 समितियों को डिजिटल करने का लक्ष्य बना रहे हैं. सहकारी समितियों में दक्षता के स्तर पर पिछले कुछ वर्षों में आई खामियों पर उन्होंने कहा कि हम पारदर्शिता में सुधार करके और इन संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण के जरिये उन्हें महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखला का खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

नाबार्ड सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक डेटा वेयरहाउस भी बना रहा है। यह करीब छह महीने में तैयार हो जाना चाहिए। सूक्ष्म वित्त पहुंच के संबंध में क्षेत्रीय असमानता की ओर इशारा करते हुए शाजी ने कहा कि पूर्व और दक्षिण की ओर इसका झुकाव अधिक है। इन दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त पहुंच करीब दो-तिहाई है, जबकि उत्तर, मध्य तथा पश्चिम सहित शेष भारत में केवल एक-तिहाई है।